PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 16 ▸ Mumbai ▸ Friday, 22 May to 28 May 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

भारत से 8000 किमी. दूर मिलेंगे मोदी-ट्रंप

नई दिल्लीः पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्द मुलाकात हो सकती है। दरअसल, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों नेता जून में फ्रांस में आयोजित होने वाली जी 7 बैठक के दौरान मुलाकात कर सकते हैं। (शेष पेज-5 पर देखें)

पीएम मोदी भी होंगे शामिल

मार्च में स्पष्ट हो गया था कि पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। उस दौरान फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और उनके साथ बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर खुशी जताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 17 जून को होने वाले एवियन शिखर सम्मेलन में शामिल होने की बात पक्की कर दी है। मंत्रियों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि दुनिया की बड़ी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय दोस्ती व एकजुटता को बढ़ाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है।

यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आदेश

सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफार्म होगी अनिवार्य

लखनऊः उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए भी यूनिफॉर्म अब अनिवार्य होगा। अभी ज्यादातर विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्र अपने मनपसंद कपड़े पहनकर आते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनुशासन सख्ती से बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म को अनिवार्य किए जाने के सख्त निर्देश दिए। यही नहीं शिक्षकों को कोई ऐसा कृत्य न करने की नसीहत दी जिससे उनकी गरिमा और महिला को ठेस लगे। जनभवन में जननायक चंद्र शेखर विश्वविद्यालय बलिया से संबद्ध कॉलेजों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल कई महत्वपूर्ण निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के लिए दिए। अभी प्रदेश में कुछ महिला डिग्री कॉलेजों और सहशिक्षा वाले डिग्री कॉलेजों में तो यूनिफॉर्म की व्यवस्था है लेकिन बाकी कहीं नहीं है। ऐसे में अब सभी विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय अपने मनपसंद रंग और डिजाइन की यूनिफॉर्म छात्रों के लिए लागू करेंगे जिससे कैंपस में पढ़ाई के दौरान एकरूपता होगी।

छात्र-छात्राओं के हित में बनें कमेटियां

■ राज्यपाल ने कहा कि कई बार विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने खुलकर अपनी समस्याएं नहीं रख पाता। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में विभिन्न कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें छात्र-छात्राएं भी शामिल हों। ऐसी समितियों के माध्यम से वे अपनी समस्या ढंग से बता सकेंगे और समाधान होगा। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने प्रदेश के महिला छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने का भी आदेश दिया।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षक की करतूत पर सख्त रुख

■ लखनऊ विश्वविद्यालय में जूलोजी विभाग के शिक्षक डा. परमजीत सिंह के एक छात्रा को जानबूझकर परेशान किए जाने और पर्चा लीक किए जाने की घटना को देखते हुए प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में दो टूक कहा कि शिक्षक कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे उनकी गरिमा और महिमा को ठेस लगे।

संक्षिप्त खबरें

यूपी पिछड़ा आयोग के चेयरमैन बने राम औतार सिंह

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति राम औतार सिंह को पंचायत चुनाव में आरक्षण के निर्धारण के मकसद से गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। कमीशन में चेयरमैन राम औतार सिंह के अलावा रिटायर्ड दो एडीजे और दो आईएएस अफसर भी सदस्य रखे गए हैं। रिटायर्ड अपर जिला जज में बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, जबकि रिटायर्ड आईएएस अफसर में अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह शामिल हैं। सरकार ने आयोग को छह महीने का कार्यकाल दिया है, जिसकी सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायत चुनावों का रास्ता खुलेगा। यूपी में पंचायत चुनाव अब विलंबित हो चुकी है।

बिहार में 5 आईपीएस और 8 डीएसपी का ट्रांसफर

पटनाः बिहार में नई सरकार बनने के बाद तबादलों का दौर जारी है। सम्राट चौधरी सरकार ने एक बार फिर बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत पांच आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और 8 डीएसपी रैंक के बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की ट्रांसफर और नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया। नवगछिया पुलिस जिला में नए एसपी की तैनाती की गई है। वहीं, पटना सिटी के एसडीपीओ-2 को पूर्णिया भेज दिया गया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को एडीजी सुरक्षा लगाया गया है, उनके पास एडीजी (बजट, अपील एवं कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सीआईडी के एसपी आदित्य कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14 में समादेष्टा की पोस्टिंग दी गई है।

मैदानों से पहाड़ों तक आसमान से बरस रही आग

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। हालात ये हैं कि हीट मैप में भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी शहर भारत के हैं, जिसमें से 40 शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें बांदा सबसे गर्म है, जहां तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी गर्मी अपने पीक पर है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चिंता की बात ये है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। इन जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी

है कि दिन में तो गर्मी पड़ ही रही है। रात में भी हीटवेव जैसे हालत रहेंगे। तापमान का 48 डिग्री से ऊपर जाना एक चेतावनी की तरह है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पेड़ पौधों की कमी है। इस इलाके में खनन भी गर्मी बढ़ने की बड़ी वजह है। पहाड़ों के कटान से की वजह से गर्म हवाएं सीधे मैदानी इलाके में पहुंच रही हैं। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ उन पहाड़ों पर भी बज रहा है, जहां लोग गर्मी में छुट्टियां मनाने जाते हैं। (शेष पेज-5 पर देखें)

यूपी भाजपा में बड़े चेहरों की होगी एंट्री

नई दिल्ली/लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार बीते सप्ताह हुआ है। विधानसभा चुनाव में एक साल का वक्त बचा है और अब उससे पहले पार्टी संगठन के पेच भी कस लेना चाहती है। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव के दौरान मशीनरी कमजोर न रहे। 2014 से अब तक भाजपा ने यूपी में सभी चुनाव इलेक्शन मशीनरी यानी संगठन के दम पर ही जीते हैं। ऐसे में सरकार को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण फिट करने के बाद भाजपा की नजर अब संगठन की ओर है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इसी महीने के अंत तक यूपी भाजपा में पदाधिकारी चुन लिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी फिलहाल इसी को लेकर मंथन में

जुटे हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किन लोगों को संगठन में चांस मिलेगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक भाजपा संगठन में ऐसे लोगों को मौका देना चाहती है, जिनका लंबा अनुभव है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं और उन्हें संगठन का आदमी कहा जाता है। भाजपा में संगठन का आदमी ऐसे लोगों को कहा जाता है, जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और विचार से लेकर पार्टी की रीति-नीति तक की अच्छी जानकारी रखते हों। भाजपा के एक सीनियर लीडर ने कहा कि कम से कम 60 पदाधिकारी ऐसे होंगे, जो संगठन की समझ रखते हों। इन नियुक्तियों में जातीय संतुलन से ज्यादा संगठन की समझ को महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन को साधा जा सकता है। दरअसल कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने जातीय संतुलन का ध्यान रखा था। ज्यादातर ओबीसी और दलित वर्ग के नेताओं को ही तवज्जो मिली थी, लेकिन संगठन में ऐसा नहीं होगा। (शेष पेज-5 पर देखें)

शरद पवार ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ

बोले- वे भारत का मान बढ़ाने में जुटे

मुंबईः एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भी हमेशा देश के भविष्य और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भी हमेशा देश के भविष्य और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। (शेष पेज-5 पर देखें)

प्यूपिल्स टाइम्स

संपादकीय

प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी

पांच देशों के अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि यदि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से सुधार नहीं होता तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीब हो जाएगी। उन्होंने यह चेतावनी देते हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और उसके चलते होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से उपजे संकट का उल्लेख किया। उनका यह कहना भी सही है कि यह दशक आपदा का दिखता है, क्योंकि पहले कोविड महामारी ने विश्व को आर्थिक संकट में धकेला, फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। इसके दुष्परिणामस्वरूप खाड़ी देशों से होर्मुज समुद्री मार्ग के जरिये होने वाली ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो गई। यह आपूर्ति अब तक बाधित है। इसके चलते पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आने के कारण लगभग सभी देशों को पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले दिनों भारत ने भी उनके दाम बढ़ाए। इसके आसार हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम फिर से बढ़ाने पड़ सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और महंगाई बढ़ती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात और कोई नहीं हो सकती कि उनमें से तमाम के सामने फिर से गरीब होने का संकट खड़ा हो गया है। यह खतरा केवल भारतीयों के सामने ही नहीं, अन्य विकासशील एवं निर्धन देशों के लोगों के सामने भी है। युद्धों से केवल ऊर्जा आपूर्ति ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ता है और इसके नतीजे में भी महंगाई बढ़ती है। इसमें संदेह है कि विश्व की एक बड़ी आबादी के समक्ष संकट बढ़ जाने के बाद भी शक्तिशाली देश जिम्मेदारी का परिचय देंगे और टकराव एवं तनाव कम करने के लिए सक्रिय होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति से तमाम देशों को तंग किया है। अब यह भी स्पष्ट है कि उसने नतीजों की परवाह किए बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। चूंकि इसका ठिकाना नहीं कि विश्व में स्थिरता और शांति कब आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार ऐसी नीतियों पर ध्यान दे, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वास्तव में समर्थ बना सकें। कल्याणकारी नीतियां वोट के लिए नहीं, गरीब तबके को वास्तव में सबल बनाने के लिए चलाई जानी चाहिए।

छात्रों का आत्मघात : छात्रों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को पहचानें

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में दो महीनों के भीतर चार छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केवल एक संस्थान की त्रासदी एवं नाकामी नहीं हैं, बल्कि पूरे भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता पर लगा गहरा प्रश्नचिह्न हैं। ये घटनाएं हमें झकझोरती हैं कि आखिर वह कौन-सी परिस्थितियां हैं, जिनमें देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं जीवन से हार मानने को विवश हो जाती हैं। कोई भी युवा, जो कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरकर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचता है, वह सहज रूप से जीवन का परित्याग नहीं करता, वह तब यह निर्णय लेता है जब उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत विफलताओं का सम्मिलित परिणाम है। एक बड़ा सवाल है कि इस तरह छात्रों का आत्मघात करना क्या सपनों का बोझ है या सिस्टम की नाकामी? आज भारत का भविष्य कहे जाने वाले युवा जिस मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं, वह अभूतपूर्व चिन्ताजनक है। कोटा जैसे शिक्षा नगरों में हर वर्ष दर्जनों छात्र आत्महत्या करते हैं। इन घटनाओं को हम आंकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक जीवित सपना, एक संघर्षरत परिवार और टूटती उम्मीदों की कहानी होती है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य शिक्षा केंद्रों में बढ़ती आत्महत्याएं इस बात का संकेत हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं। यह केवल पढ़ाई का दबाव नहीं है, यह उस मानसिक संरचना का संकट है, जिसमें सफलता को जीवन का पर्याय बना दिया गया है और असफलता को जीवन का अंत। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा

संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक घटनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई, इसके बाद एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्थान है। यह तथ्य इस धारणा को तोड़ता है कि केवल कमजोर छात्र ही मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे प्रतिभाशाली और संवेदनशील छात्र ही अक्सर सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। यहां प्रश्न केवल संस्थानों का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का भी है जिसने सफलता को एक संकीर्ण परिभाषा में बांध दिया है। परिवार अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है। अभिभावक अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के मन पर इतना भारी पड़ता है कि वे स्वयं को एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, एक इंसान की तरह नहीं। जब यह प्रोजेक्ट असफल होता है, तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है। शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी इस संकट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को ज्ञान तो देती है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। उन्हें बताया जाता है कि गणित कैसे हल करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। उन्हें भौतिकी के नियम याद कराए जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है। परिणामस्वरूप, जब वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से सामना करते हैं तो वे टूट जाते हैं। आज के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध भी बदल गया है। पहले शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक होते थे। आज यह संबंध औपचारिक हो गया है। कई शिक्षक अपनी भूमिका को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखते हैं। वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके भावनात्मक संघर्षों और उनके आंतरिक द्वंद्व को समझने का प्रयास नहीं करते। यह दूरी छात्रों को और अधिक अकेला बना देती है। विचित्र है कि जो देश दुनिया भर में अपनी संतुलित जीवनशैली एवं अहिंसा के लिये जाना जाता है, वहां के शिक्षा-संस्थानों में हिंसा का भाव पनपना एवं छात्रों के आत्महंता होते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रहा है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों एवं खौफनाक दुर्घटनाओं के आंकड़ों ने शासन-व्यवस्था के साथ-साथ समाज-निमार्ताओं को चेताया है और गंभीरतापूर्वक इस विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक समस्या पर विचार करने के लिये जागरूक किया है, लेकिन क्या कुछ सार्थक पहल होगी? बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपनी कार्यशैली एवं परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन करें ताकि छात्रों पर बढ़ते दबावों को खत्म किया जा सके।

उर्वरक उपयोग में 50 प्रतिशत कमी से खेती-किसानी में आएगा क्रान्तिकारी बदलाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले दिनों देशवासियों से किये गए सात आग्रहों में से एक आग्रह रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का आग्रह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुध उपयोग के दुष्परिणामों को लेकर गत कई सालों से गंभीर आग्रह किये जा रहे हैं। प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन सेचुरेशन स्तर पर पहुंच गया है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी और जल प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच गया है तो रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से केंसर जैसी बीमारियों का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है। होना तो यहां तक लग गया है कि अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले किसान और प्रदेश अपने दैनिक उपभोग के लिए जैविक खाद्यान्न या अन्य प्रदेशों के खाद्यान्न के उपयोग पर जोर देने लगे हैं। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि देश में लाख प्रयासों के बावजूद रासायनिक उर्वरकों का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशों से 979 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात में से ईंधन के बाद बहुत अधिक आयात राशि उर्वरकों पर भी व्यय होती है। देश में करीब 600 लाख टन उर्वरकों की खपत है तो 2030 तक 700 से 800 लाख टन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तस्वीर का एक पक्ष यह है कि रासायनिक उर्वरकों में देश की मांग के शत-प्रतिशत पोटाश की विदेषों से आयात पर निर्भरता है तो फास्फेट के तकरीबन 90 प्रतिशत और यूरिया के करीब 25 प्रतिशत तक आयात पर निर्भरता है। मजे की बात यह भी है कि यूरिया की आयात निर्भरता तो करीब 25 प्रतिशत तक है पर यूरिया उत्पादन के लिए काम में आने वाली प्राकृतिक गैस की जरुरत करीब 80 प्रतिशत तक विदेशों से आयात से ही संभव हो पाती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार रासायनिक उर्वरकों पर दो लाख करोड़ के आसपास अनुदान राषि दी जा रही है। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कटौती का आग्रह किया है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने के लिए जहां एक और जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं पीएम प्रणाम योजना में राज्यों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री का आग्रह है कि 10 प्रतिशत फर्मेंटेड खाद का उपयोग बढ़ाकर किसान बड़ा सहयोग दे सकते हैं। जून 2023 में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के तीन साल के औसत उपयोग से खपत कम करने पर अनुदान के रुप में बचाई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के रुप में देने की व्यवस्था की गई है। इसमें से 70 प्रतिशत राशि गांवों में वैकल्पिक उर्वरक यानी जैविक खाद उत्पादन व तकनीक के विस्तार पर व्यय करने पर जोर दिया जा रहा है वहीं 30 प्रतिशत राशि रासायनिक उर्वरकों की खपत करने के लिए काश्तकारों को जागरुक करने, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने आदि पर व्यय करने का प्रावधान है। विषेषज्ञों का मानना है कि फर्मेंटेड खाद के

उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में अच्छी खासा कमी लाई जा सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फर्मेंटेड खाद मिलाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री बीजेयूआर कार्यक्रम के तहत मिट्टी की जांच का जो व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि खेत की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग किया जाए। अंधाधूंध उपयोग को रोक कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाएं रखना है। एक बात तो लगभग सबके संज्ञान में आ गई है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण खेतों की मिट्टी की उपजाउ क्षमता प्रभावित हो रही है तो भूजल का अत्यधिक दोहन होने से भू जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है वहीं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हो रहा है। जैविक विविधता प्रभावित हो रही है तो खेती के सहायक कीटनाशकों का अस्तित्व ही समाप्त होने को है। इसके अलावा खाद्यान्नों के विषैला होने व इन खाद्यान्नों के उपयोग से बीमारियों का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इतना सबकुछ होने के बावजूद रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। 2025-26 के आंकड़ों की ही बात करें तो यूरिया में 138 प्रतिशत, डीएपी के उपयोग में 94 प्रतिशत और एनपीके के उपयोग में 83 प्रतिशत के आसपास बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आग्रह के निहितार्थ को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आग्रह इस मायने में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सरकार देश की जरुरतों को पूरा नहीं कर पा रही। अपितु गंभीर चिंतन की बात यह है कि हम परंपरागत खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी और जल-मिट्टी, वायु के प्रदूषण को कम करने में भागीदार बन सकते हैं। केवल 10 प्रतिशत फर्मिंटेड खाद मिलाने से ही बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। 50 प्रतिशत तक आयात निर्भरता कम की जा सकती है। आज हम रुस, ओमान, सउदी अरब, मोरक्को, चीन आदि पर उर्वरकों के आयात के लिए निर्भर है। और अरबो डालर आयात पर खर्च करके भी प्रदूषण और सेहत से खिलवाड़ पा रहे हैं। हांलाकि आज अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आसन्न संकट को देखते हुए दूरदृष्टि पूर्ण 7 आग्रहों को प्रतिपक्ष आलोचना के स्तर पर ले रहा है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि पीएम प्रणाम कार्यक्रम जून 23 से चलाया जा रहा है तो पीएमबीजेयूआर कार्यक्रम जो कि खेत की मिट्टी की जांच से जुड़ा कार्यक्रम है वर्षों से जारी है। इसके साथ ही आज कृषि वैज्ञानिक बार बार आग्रह कर रहे हैं कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग घातक स्तर पर पहुंच रहा है। पंजाब और उससे सटते इलाकों में खेती के हालात बयां कर रहे हैं। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत कमी के आग्रह को सकारात्मक लिया जाना चाहिए। इस बहाने हमें खेती को सही दिशा देने का अवसर मिला है। खरीफ की बुवाई में ही इस पर अमल किया जा सकता है। खेती और पर्यावरण से जुड़े सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं को प्रोएक्टिव रोल अपनाते हुए आगे आना होगा। यह एक अवसर मिला है और इस अवसर का सकारात्मक उपयोग को देश की खेती किसानी को नई दिशा दी जा सकती है।

प्यूपिल्स टाइम्स

महाराष्ट्र बनेगा 'संपन्न ऊर्जा' राष्ट्र का आधार

6.5 लाख करोड़ के निवेश से बनेगी 25 हजार मेगावाट अणुऊर्जा

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 'संपन्न ऊर्जा' राष्ट्र बनाकर देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य पूरी तत्परता से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि स्वच्छ ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में राज्य में होने वाला निवेश निश्चित रूप से देश को संपन्न ऊर्जा राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। उन्होंने राज्य में अणुऊर्जा निर्माण में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को पूर्ण सरकारी सहयोग का आश्वासन भी दिया। मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य सरकार और चार प्रमुख कंपनियों के बीच अणुऊर्जा निर्माण के लिए सामंजस्य करार किए गए। इन कंपनियों में एनटीपीसीएल, अदानी पावर कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी (बजाज समूह) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और अणुऊर्जा इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निवेश से न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने संबंधित कंपनियों को प्रकल्प स्थलों का सर्वेक्षण करने और योजना को गति देने का निर्देश दिया। इन करारों के तहत राज्य में कुल 6,50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 25,400 मेगावाट अणुऊर्जा का उत्पादन और 1,23,500 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

मुंबईकरों को बिजली बिल में राहत

दिन में इस्तेमाल होने वाली बिजली होगी सस्ती

मुंबई: बोरीवली में स्थानीय भाजपा विधायक संजय उपाध्याय और बिजली प्रदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीएमसी, टाटा पावर और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के उच्च अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस प्रकार की यह पहली और ऐतिहासिक बैठक रही, जिसमें जनता की बुनियादी समस्याओं के निवारण और भविष्य की योजनाओं पर गहराई से चर्चा की गई। बैठक के बाद संजय उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कोशिशों के कारण आने वाले दिनों में मुंबईकरों को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच उपयोग की गई बिजली मीटर के प्रति यूनिट पर 55 पैसे चार्ज कम किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के क्रियान्वयन के बाद उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली पर सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष 55 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी, जिसे अगले वर्ष और बढ़ाया जाएगा। यह लाभ सीधे ग्राहकों के खातों और बिलों में ट्रांसफर किया जाएगा। शहर में कई जगहों पर अवैध रूप से मीटर बांटे जाने और टाटा अदाणी की हाई-टेंशन बिजली लाइनों के ठीक नीचे लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों (अतिक्रमण) पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सुरक्षा के मद्देनजर इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के नियमों को कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं।

योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जा रहे सोलर पंप

■ योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे उनके घरों व खेतों तक किफायती बिजली पहुंच रही है। इसी उत्पादन लागत में हुई कटौती का लाभ शहरी उपभोक्ताओं को भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से मिलने जा रहा है। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होने और आम जनता को आर्थिक राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।

एजेंसियों में समन्वय और सड़कों की खुदाई पर रोक

■ अक्सर विभिन्न विभागों (बीएमसी और उपयोगिता प्रदाताओं) में तालमेल न होने के कारण नई बनी सड़कों को दोबारा खोद दिया जाता है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता खराब होती है। बैठक में तय हुआ कि सड़क का काम शुरू होने से पहले ही सभी उपयोगिता कंपनियां अपना इंस्टॉलेशन पूरा कर लें, ताकि भविष्य में बार-बार खुदाई की स्थिति से बचा जा सके।

फर्जी लाडली बहनों को सरकार का झटका

अपात्र लाभार्थियों से वसूली की तैयारी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने साफ किया है कि जिन महिलाओं ने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, उनसे सरकार पूरी रकम वसूल करेगी। यहां तक कि कुछ पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ लिया है, उनसे भी पैसे वापस लिए जाएंगे। प्रत्येक जिले से डेटा मंगाया जा रहा है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तटकरे ने बताया कि 31 दिसंबर तक ई-केवायसी कराने की समयसीमा दी गई थी, लेकिन अनेक महिलाओं ने इसे पूरा नहीं किया। अब विभागवार डेटा की जांच की जाएगी और ऐसी महिलाओं को चिह्नित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं के नाम आरटीओ पोर्टल पर गलती से चारपहिया वाहन दर्ज हो गया है, वे जरूरी प्रमाण प्रस्तुत करें। सत्यापन के बाद उनका लाभ पुनः शुरू किया जाएगा।

राज्यभर में महिलाओं का आक्रोश

जनवरी 2026 से राज्य की 50 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खाते में किस्त नहीं आई है। अकेले सोलापुर में 4 लाख महिलाएं प्रभावित हैं। कई महिलाएं बाल विकास कार्यालयों में पहुंचकर जवाब मांग रही हैं। पोर्टल पर गलत आयकरदाता दर्ज होना, एक परिवार में दो से अधिक लाभार्थी दिखाना जैसी तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

ठाणे के तालाबों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम तेज

गौरव सिंह /ठाणे

ठाणे: ठाणे को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन समय के साथ कई तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर ठाणे शहर के शेष तालाबों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल तालाबों को पुनर्जीवित करना है, बल्कि शहर के पर्यावरण और नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। इंटीग्रेटेड लेक कंजर्वेशन नामक इस परियोजना के तहत, ठाणे के तालाबों को स्वच्छ करने, उनकी सुंदरता बढ़ाने और उनके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। महापौर ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित कर तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन में उनका सुझाव भी लिया। राज्य सरोवर संवर्धन योजना के जरिए ठाणे में तालाबों का संवर्धन और सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। जिसको देखते हुए महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ तालाबों का दौरा किया।

समुद्र से कचरा हटाने के लिए इलेक्ट्रिक बोट तैनात की गई

मुंबई : बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के बीच और आस-पास के इलाकों को साफ रखने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और बधवार पार्क इलाकों में तैरता हुआ कचरा इकट्ठा करने के लिए बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक बोट्स लगाई गई हैं। इन बोट्स के जरिए रोजाना इन इलाकों से लगभग 80 से 90 kg तैरता हुआ कचरा इकट्ठा किया जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निदेर्शों के अनुसार, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी के गाइडेंस में और डिप्टी कमिश्नर (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) किरण दिघावकर की देखरेख में बृहन्मुंबई इलाके (मुंबई शहर और उपनगर) में सफाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में, डिप्टी कमिश्नर (जोन-1) चंदा जाधव के गाइडेंस में और असिस्टेंट कमिश्नर (अ डिवीजन) गजानन बेल्लाले की लीडरशिप में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 'A' डिवीजन के भारती घर और बधवार पार्क इलाकों में दो बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक बोट्स चालू की गई हैं। ये बोट्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इनमें व्हीकल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (VTMS) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) लगा है, जिससे बोट के नेविगेशन, स्कोप और सेफ्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बोट समुद्र में तैरते अलग-अलग तरह के कचरे को इकट्ठा करने का काम ज्यादा असरदार और प्लान्ड तरीके से कर सकती हैं। इस जगह पर समुद्र के पानी में बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें, बैग और दूसरा कचरा तैरता हुआ मिलता है। इंसानी कोशिशों से इस कचरे को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल और टाइम लेने वाला काम है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अ डिवीजन ने ये दो बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक बोट चालू की हैं जो सीधे समुद्र में जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं। क्योंकि ये बोट पूरी तरह से बिजली से चलती हैं, इसलिए ये डीजल या पेट्रोल से चलने वाले दूसरे जहाजों की तरह समुद्री एनवायरनमेंट और पानी वाले जीवों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करतीं।

उत्तर मुंबई में विकास कार्यों को रफ्तार

पीयूष गोयल ने नाला सफाई और रोजगार केंद्रों की समीक्षा की

मुंबई : उत्तर मुंबई के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने मानसून से पहले की तैयारियों, युवाओं के रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।

आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए पीयूष गोयल ने डहाणूकरवाडी पुल के पास नालों की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर नालों की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नालों के पास किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण जलभराव की समस्या पैदा होती है।

तुरंत हटाया जाए अतिक्रमण

■ इसलिए मानसून में नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए इस अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के संकल्प के तहत युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कांदिवली पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र की सफलता के बाद अब क्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने दहिसर चेक नाका, ठाकुर विलेज, शिंपोली रोड, चिंचोली बंदर और मालाड पश्चिम में प्रस्तावित जगहों का मुआयना किया।

बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े का निर्देश

मुंबई में सीसी रोड का काम 31 मई तक करें पूरा

मुंबई : बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने मुंबई में सीसी रोड का काम 31 मई तक पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि सड़कों का काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जहां इस मौसम में सीसी रोड का काम मुमकिन नहीं है, वहां कंक्रीट की बजाए समतल मैस्टिक सड़कें बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, सुरक्षा और परिसर को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया है। मनपा मुख्यालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गई थी। इस बैठक में बीएमसी आयुक्त ने मुंबई में चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मनपा के क्लीनिक और अस्पतालों की इमारतें आकर्षक दिखनी चाहिए। बीएमसी के सभी अस्पतालों में कुल 14,653 बेड उपलब्ध है। नए अस्पताल बनने के बाद लगभग 4,556 और बेड जुड़ जाएंगे। मनपा के हेल्थ सिस्टम में लगभग 21,299 स्थाई कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है। सड़क कार्यों के दौरान, लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों और संवेदनशील जगहों पर पहले से मौजूद स्पीड बंध को फिर से लगाया जाना चाहिए।

मानसून से पहले सभी काम पूरे करना मुमकिन नहीं

■ ट्रैफिक सुरक्षा को और असरदार बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से थर्माप्लास्टिक मार्किंग, रंबलर स्ट्रिप्स वगैरह जैसे मॉडर्न ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि मानसून में निचले इलाकों में जलभराव रोकने के लिए मनपा का स्थाई सिस्टम तैयार रहना चाहिए। इस साल के मानसून से पहले सभी काम पूरे करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए कारगर योजना बनाई जानी चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

अब मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगा स्कूलों का स्थानांतरण

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में स्कूलों के मनमाने स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए नई और कड़ी नीति लागू कर दी है। अब स्कूलों को केवल खतरनाक इमारत, प्राकृतिक आपदा, विकास परियोजना या अपर्याप्त भौतिक सुविधाओं जैसी विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण की अनुमति मिलेगी। नए नियमों के तहत आरटीई मानकों का पालन, विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण, दूरी सीमा का पालन और अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन जैसी शर्तें अनिवार्य कर दी गई हैं। सरकार का दावा है कि इस फैसले से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होने से बचेगी और स्कूलों के नाम पर होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।

जारी किए नए कड़े नियम

- महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा व खेल विभाग द्वारा 15 मई को जारी शासनादेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्थानांतरण के लिए सख्त और पारदर्शी मानदंड तय किए गए हैं।
- नई नीति के अनुसार अब स्कूलों को केवल अपवादात्मक परिस्थितियों या भौतिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।
- जर्जर और खतरनाक इमारत, प्राकृतिक आपदा या विकास परियोजना से प्रभावित स्कूलों को स्थानांतरण की मंजूरी मिल सकेगी। इसके अलावा किराए की इमारत से संस्था की अपनी इमारत में जाना, किराया करार समाप्त होना या अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बेहतर भवन में स्थानांतरण भी मान्य कारण होंगे।
- सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए कई अनिवार्य शर्तें तय की हैं। इनमें सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग से दूरी प्रमाणपत्र, स्थानीय स्वराज्य संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी होगा।

महाराष्ट्र में सुरक्षा नियम कड़े होने से

ई-बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे ई-बाइक एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि वे सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने सोमवार, 17 मई को कहा कि सरकार पैसेंजर सेफ्टी, ड्राइवर वेरिफिकेशन या ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं करेगी। यह चेतावनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की राज्य में ई-बाइक सर्विस प्रोवाइडर्स के कामकाज का आकलन करने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद आई। अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। इनमें ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लाइसेंस स्टेटस और ऐप मैनेजमेंट सिस्टम में संभावित कमियां शामिल थीं। सरनाइक ने कहा कि राज्य सरकार एक डिटेल्ड पॉलिसी तैयार कर रही है जो ई-बाइक सर्विस के तहत सिर्फ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को ही चलाने की इजाजत देगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली बाइक इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ड्राइवरों को किसी भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करनी होगी। सरकार रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एग्रीगेटर एप्लिकेशन का एक्सेस देने की भी योजना बना रही है। इससे अधिकारी हर प्लेटफॉर्म से जुड़े वाहनों को ट्रैक कर सकेंगे। अधिकारियों ने एक ही दिन में कई एग्रीगेटर कंपनियों के लिए काम करने वाले ड्राइवरों पर भी चिंता जताई। सरकार अब एक ऐसे नियम पर विचार कर रही है जो सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए ड्राइवरों को हर दिन सिर्फ.एक प्लेटफॉर्म पर काम करने पर रोक लगा सकता है।

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Dadar - Borivali - Virar
Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
1. We get personal attention but in class its not there. 4. Its Time saving but in classes time wasted.
2. We get Result guaranty but classes no result guaranty. 5. Here efficiency 10 times more than classes in classes low efficiency.
3. Syllabus Completion in our hand in classes we cannot complete in our time. 6. Class Time as per students convenience, in classes as per their time
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS • SHOPS • BUNGALOWS
LANDS • REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
24 HOURS EMERGENCY
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane.
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

प्यूपिल्स टाइम्स

दिनभर की दौड़, रातभर का जागरण: आयुर्वेद में नींद का विज्ञान

अत्यधिक परिश्रम के बाद भी नींद क्यों नहीं आती?

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

आयुर्वेद की दृष्टि में आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में अनेक लोग दिनभर अत्यधिक कार्य करने के बाद भी रात्रि में सहज नींद नहीं ले पाते। शरीर थका होता है, किंतु मन शांत नहीं हो पाता। आयुर्वेद इस स्थिति को अनिद्रा मानते हुए मुख्यतः वात और पित्त दोष के असंतुलन से जोड़ता है। अत्यधिक मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक मोबाइल या स्क्रीन का उपयोग, असमय भोजन तथा भविष्य की चिंता ये सभी कारण मस्तिष्क को निरंतर सक्रिय बनाए रखते हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति को सोने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। आयुर्वेद में निद्रा को स्वस्थ जीवन के प्रमुख आधारों में स्थान दिया गया है। इसके अनुसार केवल दवा नहीं, बल्कि संतुलित जीवनशैली ही स्थायी समाधान है। रात्रि में हल्का भोजन, सोने से पूर्व मोबाइल और टीवी से दूरी, शांत वातावरण तथा नियमित समय पर शयन लाभकारी माना गया है। तलवों एवं सिर पर तिल तेल या ब्राह्मी तेल की हल्की मालिश भी मानसिक शांति देने में सहायक मानी जाती है। गुनगुने दूध में अल्प मात्रा में जायफल या घी का सेवन तथा अनुलोम-विलोम एवं भ्रामरी प्राणायाम जैसी विधियाँ स्वाभाविक निद्रा में सहायता कर सकती हैं।

आयुर्वेद का मूल संदेश स्पष्ट है स्वस्थ नींद केवल आराम नहीं, बल्कि शरीर और मन के संतुलन का आधार है। संयमित दिनचर्या ही अनिद्रा का सबसे प्रभावी उपचार है।

लगातार बैठे रहना और कम नींद...

कैसे डिजिटल लाइफस्टाइल युवाओं को बना रही है हाई बीपी का मरीज?

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित बीमारी नहीं रह गई है। आजकल 30 और 40 साल के युवा भी हाई बीपी की समस्या का शिकार हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आज की डिजिटल होती लाइफस्टाइल है। स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, लंबे समय तक बैठे रहना, काम का लगातार तनाव, अनियमित खान-पान और नींद की कमी इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं।

क्यों बढ़ रहा बीपी? : आजकल कई लोग लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने 10-12 घंटे बिताते हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जो वजन बढ़ने और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और ये सभी कारक सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख कारक लगातार होने वाला मेंटल स्ट्रेस है। वर्क प्रेशर, डेडलाइन, फाइनेंस से जुड़ी चिंताएं और ऑफिस के बाद भी आराम न कर पाना शरीर को लगातार तनाव की स्थिति में रखता है। इससे एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में लगातार बढ़ोतरी होती है।

नींद की कमी भी जिम्मेदार: नींद की कमी भी उतनी ही खतरनाक है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। नींद की खराब गुणवत्ता, देर रात तक इंटरनेट ब्राउज करना, बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखना और स्लीप साइकिल में गड़बड़ी शरीर की नेचुरल रिकवरी प्रोसेस में बाधा डालती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है।

रोजमर्रा की आदतें : इन सबके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी खान-पान की आदतें इस समस्या को और भी बदतर बना रही हैं। प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा खाना, नमक की ज्यादा मात्रा, ज्यादा कैफीन पीना, धूम्रपान, शराब और व्यायाम की कमी, कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं।

कैसे करें बचाव : अच्छी खबर यह है कि इससे बचना संभव है। इसके लिए आपको बस जीवनशैली में कुछ सरल बदलाव करने पड़ेंगे। नियमित व्यायाम, स्क्रीन टाइम सीमित करना, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, नमक कम करना, तंबाकू से परहेज करना और समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराना जरूरी है।

कमजोर इम्युनिटी से बढ़ता है टीबी का खतरा

डाइट में आज ही शामिल करें ये पोषक तत्व

जब शरीर को भोजन के जरिये पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसी में एक सबसे गंभीर तरह की बीमारी है- ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। इससे बचने के लिए खानपान का ध्यान रखें।

संक्रमण रोकने के लिए खानपान

>> टीबी के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें भोजन के माध्यम से पर्याप्त प्रोटीन उपलब्ध कराया जाए।

>> भोजन में दालें, दूध, दही, अंडा, नान वेज आदि आवश्यक हैं।

>> वजन में गिरावट को रोकने के लिए कैलोरी की अधिकता वाला भोजन देना चाहिए।

>> कैलोरी की भरपाई के लिए भोजन में पर्याप्त अनाज, खिचड़ी, केले, सूखे मेवे और मौसमी फल आवश्यक है।

>> इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों की जरूरत होती है।

>> विटामिन-सी, आयरन की प्रचुरता वाले फल-सब्जियां जैसे आंवला, संतरा आदि खाने से इम्युनिटी बढ़ती है।

>> हाइड्रेशन का खयाल रखना जरूरी है, ताकि साइड इफेक्ट्स कम रह सके। इसके लिए पानी, नींबू पानी, नारियल पानी लेते रहना चाहिए।

अगर पेट में लगातार दर्द बना रहता है तो इसे अनदेखा न करें। जल्द से जल्द किसी कुशल चिकित्सक से आपको संपर्क करना चाहिए। गर्मी के दिनों में उच्च तापमान और शरीर में पानी की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन के कारण पेट संबंधी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। यही नहीं इन दिनों शरीर से पसीने के रूप में भी काफी मात्रा में पानी निकल जाता है। पानी की कमी होने पर पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है। इस कारण पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शरीर में पानी की कमी के कारण पेट में एसिड की मात्रा भी काफी बढ़ जाती है। इससे पेट और सीने में जलन होने लगती है। पानी की कमी होने पर कब्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही ब्लोटिंग अर्थात पेट फूलने और पेट में गैस बनने की समस्या भी सामने आती है।

पेज-1 का शेष

भारत से 8000 किमी. दूर मिलेंगे मोदी-ट्रंप...

हालांकि, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक ओर जहां अमेरिका, ईरान के साथ युद्ध में जुटा हुआ है। वहीं, इस युद्ध की आंच भारत को ईंधन के मोर्चे पर झेलनी पड़ रही है। फ्रांस में यह बैठक 15 से 17 जून को होने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप फ्रांस में जी7 बैठक में शामिल होंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार और अपराध सें जंग जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि ट्रंप व्यापार में अमेरिका के सहयोग, अमेरिका में बने एआई टूल्स और अहम मिनरल सप्लाई चेन पर चीन का प्रभाव कम करने समेत कई मुद्दों पर बोल सकते हैं।

यूपी भाजपा में बड़े चेहरों की होगी एंट्री...

जातीय समीकरणों को परे रखते हुए भाजपा ऐसे लोगों को महत्व देगी, जो लंबे समय से संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। भाजपा के संगठन में राज्य स्तरीय इकाई के लिए 6 क्षेत्रीय यूनिट भी हैं। इनका गठन काशी, गोरखपुर, पश्चिम यूपी, अवध, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड के नाम से किया गया है। आरएसएस भी यूपी के अंदर 6 प्रांत मानता है और उसी के अनुसार काम करता है। सूत्रों का कहना है कि इन 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी भाजपा कद्दावर नेताओं को कमान दे सकती है। बता दें कि भाजपा ने यदि यूपी में जातीय समीकरण के नाम पर सफलता पाई है तो वहीं उसकी इलेक्शन मशीनरी भी अहमियत रखती है। यही वजह है कि 2027 के चुनावी रण से पहले भाजपा चाहती है कि सारे पेच कस लिए जाएं ताकि कोई ढिलाई न रहे।

शरद पवार ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ...

अपने राजनीतिक जीवन के शुरूआती दिनों को याद करते हुए शरद पवार ने बताया कि वर्ष 1958 में 18 साल की उम्र में वे बारामती से पुणे आए थे, क्योंकि उस समय उनके गृह नगर में कॉलेज नहीं था। बाद में वे पुणे शहर यूथ कांग्रेस और फिर महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रमुख बने। पवार ने एक घटना को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात उनके जीवन के यादगार पलों में शामिल है।

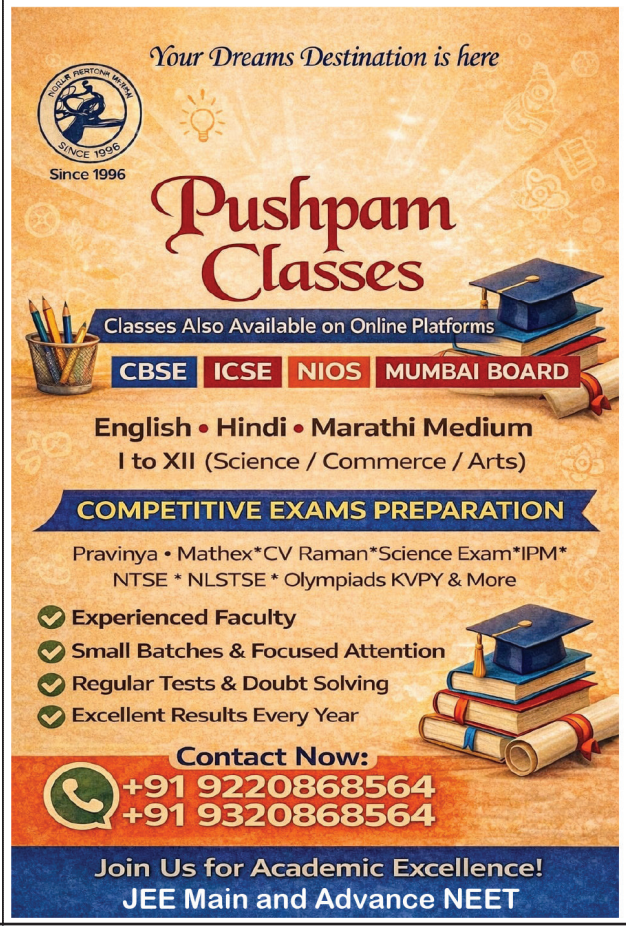

अधुना दत्तांशैः निर्धार्यते गुणवत्ता

उत्तर प्रदेशे निजी-विश्वविद्यालयानां राज्य-स्तरीया श्रेणीकरण-व्यवस्था सज्जा

उत्तर प्रदेश-सरकारः निजी-विश्वविद्यालयानां कृते नूतनां State Ranking System इति व्यवस्थां निमार्तुं सज्जा अस्ति। प्रायः द्वादश डिजिटल-मॉड्यूल-आधारितेयं व्यवस्था विश्वविद्यालयानां शैक्षणिक-गुणवत्तां, प्रशासनिक-पारदर्शितां, अनुसन्धान-क्षमतां, नियोजन-अभिलेखं तथा छात्र-सुविधानां मूल्यांकनं करिष्यति। उच्चशिक्षाक्षेत्रे उत्तरदायित्वस्य गुणवत्तानियन्त्रणस्य च दिशि एषा योजना महत्त्वपूर्णा पहलः इति मन्यते।

गतवर्षेषु प्रदेशे निजी-विश्वविद्यालयानां संख्या तीव्रतया वर्धिता अस्ति। आधुनिक-परिसराणां आकर्षक-विज्ञापनानां च मध्ये अनेकानां संस्थानां वास्तविक-शैक्षणिक-गुणवत्तायाः विषये प्रश्नाः अपि उत्थापिताः। अध्यापक-अभावः,

दुर्बला परीक्षा-व्यवस्था तथा भ्रामक-नियोजन-दावाः इत्यादयः समस्याः समये समये प्रकटिताः। अतः सरकारः अधुना 'दत्तांश-आधारित-मूल्यांकन-प्रणालीम्' आरभ्य संस्थानानि अधिकं उत्तरदायिनः कर्तुं प्रवर्तते।

प्रस्तावितेषु मॉड्यूल्सु शैक्षणिक-प्रदर्शनम्, परीक्षा-व्यवस्था, अध्यापक-गुणवत्ता, अनुसन्धानं सृजनात्मक-क्षमता च, नियोजनम्, वित्तीय-पारदर्शिता तथा डिजिटल-प्रशासनम् इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्य उद्देश्यं केवल-विज्ञापनाधारित-प्रतिष्ठां न स्वीकरोति, अपितु वास्तविक-प्रदर्शनाधारितं विश्वविद्यालयानां मूल्यांकनं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति।

एषा व्यवस्था राष्ट्रीय-स्तरीयायाः NIRF Ranking इत्यस्याः व्यवस्थायाः भिन्ना भविष्यति। यत्र NIRF प्रतिस्पर्धात्मक-श्रेणीकरणं प्रददाति, तत्र उत्तरप्रदेशस्य एषा प्रणाली निरीक्षणम्, उत्तरदायित्वं संस्थागत-अनुशासनं च अधिकं प्राधान्येन पश्यति। यदि एषा व्यवस्था प्रभावी-रूपेण प्रवर्तिता भविष्यति, तर्हि छात्राः अभिभावकाः च सरकारी-सत्यापित-दत्तांशानां आधारेण विश्वविद्यालय-चयनं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति।

तमिलनाडु 2026: सत्ता परिवर्तिता, परन्तु 'सनातन'-विषये संघर्षः यथावत्

2026 तमे वर्षे सम्पन्नाः तमिलनाडु-विधानसभा-निर्वाचनाः राज्यस्य राजनीतौ महत् परिवर्तनम् आनयन्। C. Joseph Vijay-महोदयस्य Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) दलः कांग्रेस-दलस्य समर्थनेन सरकारम् अस्थापयत्, यदा तु Udhayanifidhi Stalin-महोदयस्य DMK दलः सत्तातः बहिः अभवत्। 'मात्तरम्' अर्थात परिवर्तनम् इति घोषवाक्यं वास्तविक-सत्ता-परिवर्तने परिणतम्, किन्तु वैचारिकः संघर्षः समाप्तः नाभवत्।

१२ मई २०२६ दिनाङ्के विधानसभायाः प्रथमसत्रे विपक्ष-नेता उदयनिधि-स्टालिन-महोदयः उक्तवान्-'यत् सनातनं जनान् विभजति, तस्य समूल-नाशः भवेत्।' अस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं राष्ट्रीय-राजनीतौ नूतनः विवादः आरब्धः। भाजपा-दलः तथा अनेकाः हिन्दू-सङ्गठनाः एतत् सनातन-धर्मस्य विरोधः इति अवदन्, यदा तु DMK-दलः एतत् सामाजिक-असमानतायाः जातिगत-भेदभावस्य च विरोधरूपेण प्रस्तुतवान्। मुख्यमन्त्रिणः विजय-महोदयस्य मौनम् अत्यधिक-चचार्याः केन्द्रम् अभवत्। ते सदने उपस्थिताः आसन्, किन्तु न समर्थनम् अकुर्वन्, न च खण्डनम्। विश्लेषकाः मन्यन्ते यत् कांग्रेस-समर्थिता सरकारः द्रविड-राजनीत्या सह प्रत्यक्ष-संघर्षं परिहरितुम् इच्छति। तमिलनाडौ सत्ता परिवर्तिता, किन्तु 'सनातन बनाम द्रविड-विमर्शः' इति विवादः अद्यापि प्रवर्तमानः अस्ति।

विधि-विशेषाङ्कः

दिनाङ्कोपरि दिनाङ्कः : अधिवक्तारः न्यायस्य संरक्षकाः उत विलम्बस्य निमित्तम्स?

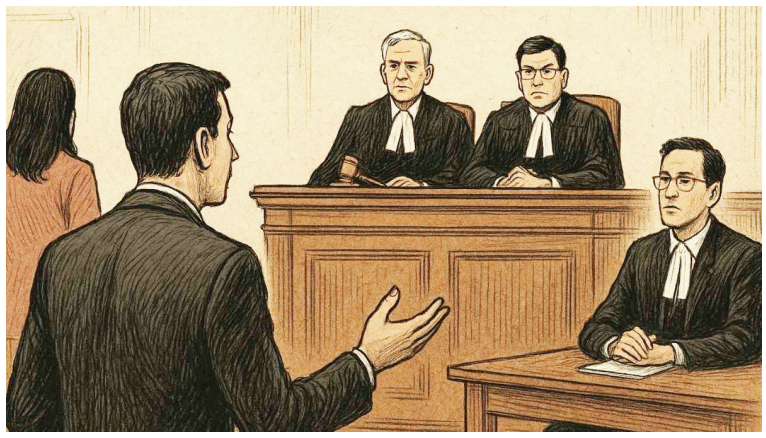

'अधिवक्तारः निष्कासिताः स्युः चेत न्यायः सुलभः भविष्यति' एषः विचारः श्रवणे सरलः, परन्तु न्यायव्यवस्थायाः वास्तविकता अत्यन्तं जटिला अस्ति।

भारतीय-विधिव्यवस्था सहस्रधाराभिः प्रक्रियाभिश्च निर्मिता दुर्गमा वीथिका इव अस्ति। दण्डसंहिता, दण्डप्रक्रियासंहिता तथा साक्ष्याधिनियमेषु सूक्ष्मापि प्राविधिकी त्रुटिः सम्पूर्णस्य व्यवहारस्य दिशां परिवर्तयितुं शक्नोति। सामान्यजनस्य कृते एतासां प्रक्रियाणाम् अवबोधनं दुष्करम्। अतः अधिवक्ता न केवलं प्रतिनिधिः, अपितु विधिमार्गदर्शकः अपि भवति। संविधानस्य अनुच्छेदौ 22(1) तथा 39अ समन्यायार्थं विधिसाहाय्यस्य महत्त्वं प्रतिपादयतः।

तथापि जनानाम्असन्तोषः निराधारः नास्ति। पञ्चकोट्यधिकाः व्यवहाराः लंबिताः सन्ति, न्यायाधीशानां संख्या च अल्पा। 'दिनाङ्कोपरि दिनाङ्कः' इति प्रवृत्त्या न्यायप्रक्रिया मन्दा व्ययबहुला च जाता। अनेकदा प्राविधिकयुक्तिषु सत्यं तिरोहितमिव दृश्यते। अन्वेषणात्मक-न्यायपद्धतिः शीघ्रनिर्णयान ददाति, किन्तु शक्तिकेन्द्रीकरणस्य भयमपि जनयति। भारतसदृशे लोकतन्त्रे जटिलव्यवहारेषु विधिविशेषज्ञानाम् आवश्यकता अद्यापि वर्तते।

समस्या अधिवक्तारः न, अपितु उत्तरदायित्वहीनता न्यायिकविलम्बश्च। समाधानं समयबद्ध-श्रवणे, अङ्कीय-न्यायपीठेषु तथा कठोर-अनुशासने निहितम्। भवतः अभिमतम् किम्? लिखन्तु: anil@pupilstimes.com

तमिलनाडूतुल्यं बङ्गेऽपि 'मात्तरम्': कुक्कुटग्रीवायां नूतन-सर्वकारस्य सामरिकम् अवधानम्

शासन-परिवर्तनं केवलं सर्वकारं न परिवर्तयति, अपितु शासनस्य प्राधान्यम् अपि परिवर्तयति। पश्चिमबङ्गे नूतन-सर्वकारस्य प्रारम्भिक-निर्णयाः अस्य परिवर्तनस्य स्पष्टं सङ्केतं ददति इव दृश्यन्ते।

कोलकाताः मुख्यमन्त्रिणः **सुवेन्दु-अधिकारि-महोदयस्य** नेतृत्वे नूतन-सर्वकारेण उत्तरबङ्गस्य सामरिकदृष्ट्या अत्यन्तसंवेदनशीलस्य **सिलीगुडी-संकटमार्गस्य** — यः सामान्यतः 'कुक्कुटग्रीवाह्व इति कथ्यते — सम्बद्धः चिरकालात लंबितः प्रस्तावः अग्रे नेतुं प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। राज्य-सर्वकारेण प्रायः **१२० एकर-परिमिता भूमिः केन्द्र-सर्वकाराय हस्तान्तरयितुम्,** तथा राष्ट्रिय-राजमार्गाणां सप्त महत्त्वपूर्णाः भागाः NHAI/NHIDCL-संस्थाभ्यः समर्पयितुम् सैद्धान्तिकी अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति।

सिलीगुडी-संकटमार्गः भारतस्य मुख्यभूमिं पूर्वोत्तरस्य अष्टभिः राज्यैः सह संयोजयन् अत्यन्तं सङ्कीर्णः भूभागः अस्ति। सङ्कीर्णतमे भागे अस्य विस्तारः प्रायः २०-२२ किलोमीटर-मात्रः मन्यते। नेपाल-भूटान-बाङ्गलादेश-सीमाभिः परिवेष्टितस्य अस्य क्षेत्रस्य महत्त्वं केवलं भौगोलिकं न, अपितु सामरिक-आर्थिक-दृष्ट्यापि अत्यन्तं गुरुत्वपूर्णम् अस्ति। सिक्किम-पूर्वोत्तर-प्रदेशानां च आपूर्ति-शृङ्खला, सैन्य-सामग्री-परिवहनम् तथा सीमावर्ति-सम्पर्कस्य

बृहद्भागः अस्मिन्नेव मार्गे अवलम्बते।

नूतन-सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत सीमा-सुरक्षां, मार्ग-अवसंरचनां तथा प्रशासनिक-समन्वयं सुदृढीकर्तुम् एषः निर्णयः आवश्यकः अस्ति। विशेषतः **NH-10** इत्यादयः मार्गाः वर्षाकाले पुनः पुनः बाधिताः भवन्ति, येन सिक्किम-पूर्वोत्तर-क्षेत्रेषु परिवहन-व्यवस्था प्रभाविता भवति। केन्द्रस्य अभिकरणानां दायित्व-प्राप्त्या मार्ग-विस्तारीकरणे, पुनर्निर्माण-कार्ये तथा निरीक्षण-व्यवस्थायां त्वरितगतेः सम्भावना वर्तते।

राजनीतिक-दृष्ट्यापि अयं निर्णयः शासन-परिवर्तनानन्तरं नीति-प्राधान्येषु जातस्य परिवर्तनस्य संकेतः इति मन्यते। पूर्ववर्तिन्याः सर्वकारस्य उपरि सीमा-वेष्टन-कार्ये भूमि-हस्तान्तरणे च विलम्बस्य आरोपाः क्रियन्ते स्म, यदा तु नूतना सर्वकारः एतत ह्वराष्ट्रीय-सुरक्षा-अवसंरचना-प्राधान्यम्ह्व इति रूपेण प्रस्तौति।

तमिलनाडौ शासन-परिवर्तनानन्तरं यथा वैचारिक-विमर्शः चचार्याम् आसीत, तथैव बङ्गे नूतना सर्वकारः सामरिक-अवसंरचनां सीमा-सुरक्षां च प्राधान्येन पश्यति इव दृश्यते। कुक्कुटग्रीवा-प्रदेशसम्बद्धः अयं निर्णयः केवलम् प्रशासनिकः उपायः न, अपितु परिवर्तमानायाः राज्य-राजनीतेः राष्ट्रीय-सुरक्षा-विमर्शस्य च मध्ये उद्भवतः नूतन-सन्तुलनस्य संकेतः अपि मन्यते।

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

भित्तीनां पार्श्वेऽपि सम्बन्धाः सन्ति

लघु-सामाजिक-नाटकम

पात्राणिः सूत्रधारः रागिणी अमनः चीकुः शारदा-नानी गुप्त-महोदयः **दृश्यम् १**

गृहस्य प्रकोष्ठः, प्रातःकालः (चलदूरभाषस्य सूचनाध्वनयः अनुवर्तन्ते। रागिणी सङ्गणक-पुटं सम्भालयति। अमनः त्वरया सज्जो भवति। चीकुः साश्रु वदति।)

रागिणी अमन! मम सभा अस्ति। चीकुं विद्यालयं कः नेष्यति?

अमनः अद्य प्रकल्पस्य अन्तिम-वेला वर्तते। अवकाशं गृहीतवान चेत वेतनं न्यूनं भविष्यति।

चीकुः अम्ब! मा गच्छ।

सूत्रधारः महानगराणां लघु-गृहेषु प्रतिप्रभातम् अयमेव संघर्षः दृश्यते— वृत्तिः, बालकः, एकाकित्वं च।

दृश्यम् २ उद्यानम् (शारदा-नानी गुप्त-महोदयश्च आसन्दिकायाम् उपविष्टौ।)

गुप्त-महोदयः गृहम् अधुना गृहवत् नानुभूयते। केवलः प्रकोष्ठः इव प्रतिभाति। **शारदा-नानी** मम पौत्रः चलदूरभाषे 'हाय नानी' इत्युक्त्वा क्षणेन पलायते। मम क्रोडः रिक्तः एव तिष्ठति। (तावदेव चीकुः धावन आगच्छति।)

शारदा-नानी एहि वत्स! त्वां दोलायाम् आरोहयामि। (चीकुः स्मित्वा अनुमोदते।)

सूत्रधारः एकतः बालकाः सन्ति येभ्यः पितामही अपेक्षिता। अपरतः पितामह्यः सन्ति याभ्यः बालकाः अपेक्षिताः।

दृश्यम ३ आवास-समितेः सभा रागिणी किमर्थं वयं परस्परस्य अवलम्बनं न भवेम? नानी चीकुं पालयिष्यति, वयं च तस्याः औषधं चिकित्सां आवश्यकताश्च निर्वहिष्यामः।

गुप्त-महोदयः किमर्थम्ह्व वयं पुनरपि एकः परिवारः भवितुं शक्नुमः?

चीकुः (धावित्वा) नानि! मम पादत्राणं बन्धय।(सर्वे मन्दं स्मयन्ति।)

दृश्यम् ४ मासत्रयानन्तरम् (उद्याने आनन्दमयं वातावरणम्। चीकुः नान्याः क्रोडे चित्रं रचयति।)

अमनः अधुना गृहम् आगच्छतः मे चिन्ता नास्ति यत चीकुः एकाकी स्यात।

शारदा-नानी मम एकाकित्वम् अपि अधुना विगतम्।

सूत्रधारः संयुक्त-कुटुम्बानि भग्नानि, किन्तु संवेदनाः अद्यापि जीवन्ति। सम्बन्धाः केवलं रक्तेन न निर्मीयन्ते, आत्मीयता अपि कुटुम्बं रचयति।

सर्वे मिलित्वा 'चलदूरभाषेण जगत संयोजयितुं शक्यते, किन्तु हृदयं केवलं सम्बन्धैः एव संयुज्यते।' 'वसुधैव कुटुम्बकम्।'

(यवनिका पतति)

BRICS stage will be decorated in 'Bharat Mandapam' of Delhi

Why will the tension between America and Donald Trump increase?

Recently, when the BRICS foreign ministers met in Delhi, China's Foreign Minister Wang Yi could not attend it as he had to stay in Beijing for a high-profile meeting between US President Donald Trump and Jinping. Now the scope of BRICS has expanded considerably in which new countries like Egypt, Ethiopia, Iran, UAE and Indonesia have been included. In such a situation, this organization represents about 49.5% of the global population and 40% of the global GDP. Also, BRICS countries now control 26 percent of the world's trade.

New Delhi: India's capital New Delhi is once again going to witness the world's biggest diplomatic stir. Russian President Vladimir Putin's visit to India for the BRICS summit to be held on 12 and 13 September has been confirmed. Along with this, there is every possibility of Chinese President Xi Jinping also coming to Delhi. If everything goes as per schedule, then this powerful 'trio' of Prime Minister Narendra Modi, Putin and Jinping will be seen on one stage in Delhi. This great gathering is being considered very important from the point of view of global politics, whose direct impact can also be seen on the strategies of US President Donald Trump. India is presiding over BRICS this year. According to sources, this mega conference can be organized in 'Bharat Mandapam' of New Delhi. Russian news agency TASS and Kremlin aide Yuri Ushakov have officially confirmed Putin's visit. Let us tell you that Putin had earlier come to New Delhi to participate in the 23rd India-Russia Annual Summit in December 2025. The most talked about aspect of this conference is the possible visit of Chinese President Xi Jinping to India. Jinping last visited India in October 2019

Big petition in Supreme Court

Aadhaar should become only a means of identification

not proof of citizenship or address

New Delhi: An important PIL has been filed in the Supreme Court regarding the increasing use and misuse of Aadhaar card in the country. It has been alleged in the petition that Aadhaar card is being used indiscriminately as proof of citizenship, place of residence and address. A demand has been made from the top court to issue strict instructions to the Central Government to limit it only as an identity card. This petition has been filed on behalf of advocate Ashwini Kumar Upadhyay. It sought direction to the Central Government, State Governments and the Election Commission of India to ensure that Aadhaar is used only to prove identity and not to authenticate citizenship, domicile, address or date of birth. The petition, filed through advocate Ashwani Dubey, raises serious legal questions on the use of Aadhaar in the new voter registration Form-6. According to the petition, accepting Aadhaar as proof of date of birth and residence for adding names to the voter list is completely against the provisions of Section 9 of the Aadhaar Act, 2016, Section 23(4) of the Representation of the People Act, 1950, and Article 14 of the Constitution.

Yogi cabinet approved

1010 bed state-of-the-art emergency center will be built in Lohia Institute

Lucknow: In the Yogi Cabinet meeting, the project related to construction of 1010 bedded Multi Specialty Emergency Center Hospital, new OPD Block and Teaching Block in the new campus of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Gomti Nagar Extension Sector-7 located at Shaheed Path was approved. Finance Minister of Uttar Pradesh Government, Suresh Kumar Khanna said that approval of Rs 855 crore 4 lakh 34 thousand has been given for this ambitious project. Under this ambitious project, a multi-specialty emergency center hospital with state-of-the-art facilities will be constructed, in which a total of 1010 beds will be established. Along with this, keeping in mind the increasing number of patients and better treatment system, a new OPD block will also be built, which will provide more organized and modern health services to the people of the state. Under the project, a new teaching block with a capacity of 200 seats will also be developed. This will provide medical students with a learning environment equipped with modern technology and resources and the quality of medical education will further improve. With the development of this new medical infrastructure, quick and expert treatment can be provided to serious patients.

Strictness on NEET re-exam, action will be taken against fake telegram channels

Education Minister Dharmendra Pradhan gave strict instructions

New Delhi: The Central Government has come in full alert mode regarding NEET-UG re-exam. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a high level meeting with security and intelligence agencies and gave instructions to conduct the examination in a safe, fair and transparent manner. Senior officials of the Education Ministry and National Testing Agency (NTA) also attended the meeting. Before the examination, the security arrangements and vulnerabilities were reviewed in detail to prevent any kind of irregularities. Along with this, the government has also adopted a strict stance on rumors and fake information spreading on social media. In a separate meeting

with representatives of big social media companies like Meta, Google and Telegram, concerns were expressed over fake paper leaks, misleading posts and Telegram channels spreading fear. Taking the matter seriously, the Education Minister identified the channels spreading fake information and gave instructions to immediately block and remove them. He said that social media companies will have to take swift action in coordination with the Education Ministry, NTA and law enforcement agencies. The government has clearly said that protecting students from rumors and maintaining people's trust in the examination system is its biggest priority.

Action will be taken against fake telegram channels: Officials said that before the exams, many Telegram channels suddenly become active and create panic among students and parents by spreading fake paper leaks, clickbait messages and unverified information. Many links lead students to fake groups and automated bots, inputs from intelligence agencies also revealed that many suspicious channels are being operated from a limited number of mobile numbers, raising suspicions of an organized network.

India has made a wonderful missile to be launched from a drone

New Delhi: India has got another major success in the defense sector. Defense Research and Development Organization (DRDO) has successfully test-fired Unmanned Aerial Vehicle (UAV) i.e. Drone Launched Precision-Guided Missile (ULPGM-V3) in Kurnool, Andhra Pradesh. This missile is capable of air-to-air and air-to-ground attack, due to which enemy tanks, drones and helicopters can be easily targeted. This test was conducted at the National Open Area Range (NOAR) located in Kurnool. Defense Minister Rajnath Singh informed about this successful test through social media and congratulated DRDO and partner companies. Micro, small and medium enterprises (MSMEs), startups and Defense Capital Procurement Partners (DcPPs) have also played an important role in the development of the missile. Rajnath Singh said that this success proves that Indian industry is now fully prepared to produce critical defense technologies.

What are the main features of this missile (ULPGM-V3)?

Weight and firepower: Weighing 12.5 kg, this missile works on 'fire and forget' technology.

Accurate target day and night: It is equipped with a solid propulsion unit, which gives it the ability to hit ranges of up to 4 kilometers during the day and 2.5 kilometers at night.

Modern Technology: Passive homing and imaging infrared (IR) seeker has been used in it. This technology helps it to aim accurately in both day and night conditions.

Communication and targeting: This missile is equipped with two-way datalink technology. It comes with different warhead options to destroy both stationary and moving targets.

Big victory for Indian defense ecosystem: Although this missile system has been designed and tested by DRDO, companies like Bharat Dynamics Limited (BDL) and Adani Defense have played a major role as partners in its construction.

BSF in action to seal the border

Survey work started after getting land from Bengal government

New Delhi: The long pending fencing project on the India-Bangladesh border now seems to be coming on the ground. After the decision to hand over the land in Changarabandha area of Jalpaiguri, BSF has started the work of survey and pillar marking.

A major step has been taken towards fencing the India-Bangladesh border in Changarabandha in Cooch Behar district. Officials of BSF and Land Reforms Department have jointly inspected the area and started the process of measurement and demarcation of land for fencing. According to sources, BSF, with the help of official maps, identified the routes through which the barbed wire fencing will pass. After this, boundaries are being decided by placing pillars at the identified places.

In which areas the work was done : This survey and marking was done mainly in Purvapada area of Changarabandha, where there was no fencing for many years. During this time, local people were also present on the spot, because part of their land has been included for the proposed fencing.

PUPILS TIMES

Friday, 22 May to 28 May 2026

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project...

130 meter long steel bridge over track successfully launched

New Delhi: Another major achievement has been achieved in the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project. A 130 meter long steel bridge has been successfully launched over the Indian Railways track near Tralsi village in Bharuch district of Gujarat. This bridge is crossing the DFCC track in the Surat-Vadodara section of the Western Dedicated Freight Corridor. Earlier, in March 2026, a 100 meter long second span was prepared at the construction site itself. The bridge is a total of 330 meters long, which includes a continuous span of 100+130 meters and a separated span of 100 meters. With this, till now 230 meter steel bridge work out of 330 meter has been completed. This 130 meter long portion was launched on 16 May 2026. The weight of this steel span, which is about 18 meters high and 15.5 meters wide, is approximately 2900 metric tons. Now the remaining 100 meter long portion will also be constructed there. After the complete bridge is ready, its total weight will be around 6100 metric tons. The age of these steel bridges, manufactured in the carbon factory located in Umargaon, Jarat, is considered to be around 100 years. About 1.21 lakh high strength bolts have been installed in this 130 meter long section. It was built on a temporary structure at a height of 14 meters from the ground and was moved forward with the help of a special automatic system. During the bridge launching, special traffic arrangements were made on the goods train track so that there is minimal impact on the movement of freight trains and the work can be completed safely. A total of 28 steel bridges are to be built in the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Corridor. Of these, work on 14 out of 17 steel bridges in Gujarat has been completed.

Plan for 28 steel bridges to last for 100 years

These steel bridges, manufactured at the Carbon Factory Workshop in Umargaon, Gujarat, have been designed keeping in mind the lifespan of 100 years. Out of 17 steel bridges, 14 steel bridges have been completed in Gujarat. 28 steel bridges are planned for the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Corridor. Bullet train will run first in Gujarat between Surat and Bilimora.

Bullet train will run next year

Railway Minister Ashwini Vaishnav has said that the Bullet Train will run on August 15 next year. Before this, trial run of bullet train will be done in Gujarat. After the completion of the track work between Surat and Bilimora, OSE, noise barrier and other works are being completed on it. This part was inspected by PM Modi. There are 12 stations on the entire route of Mumbai Ahmedabad Bullet Train. The bullet train will run at a speed of 320 kilometers per hour.

"Towards Tissue-Level Repair"

The Emerging Scientific Revolution of Stem Cell Therapy

Dr. Arvind singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

Imagine a future where damaged organs in the human body begin to heal themselves; where even after a severe spinal injury, the hope of walking again remains alive; where weakened heart muscles regain their strength. In modern medical science, Stem Cell Therapy has emerged as a symbol of this transformative possibility.Stem cells are unique biological cells often referred to as the body's "master cells." Their defining characteristic is the ability to differentiate into specialized cell types such as blood, nerve, muscle, or skin cells according to physiological requirements. Scientists increasingly regard them as the foundation of regenerative medicine and tissue engineering. When tissues are damaged due to disease, trauma, or aging, the body's natural regenerative capacity is often limited. Stem cell therapy attempts to restore or regenerate these damaged tissues using specialized cellular mechanisms (differentiation, immunomodulation, paracrine signaling) rather than merely suppressing symptoms. Therapies today mainly utilize mesenchymal stem cells (MSCs) derived from bone marrow or adipose tissue, along with induced pluripotent stem cells (iPSCs), which are reprogrammed from adult somatic cells.In recent years, the convergence of stem cell biology with gene-editing technologies such as CRISPR-Cas9 has expanded the scope of regenerative medicine. Researchers are exploring methods to genetically correct defective cells before transplantation, thereby moving treatment closer to the "genetic level" of precision medicine. At present, stem cell-based interventions are being actively explored in clinical trials for conditions such as Parkinson's disease, spinal cord injuries, cardiovascular disorders, diabetes, and neurodegenerative illnesses. However, outside hematological malignancies, bone marrow transplantation, and limited orthopedic applications, most therapies have not yet achieved routine regulatory approval. The greatest promise of stem cell therapy lies in its potential to repair and Rejanrete damaged tissues rather than only managing disease manifestations. Nevertheless, the field continues to face major scientific and ethical challenges, including risks of teratoma formation, immune rejection, and the rapid growth of unregulated "stem cell tourism" clinics, particularly in developing countries. In India, the ICMR-DBT 2017 Guidelines permit only bone marrow transplantation and select approved clinical trials, while most commercial stem cell therapy claims remain scientifically unapproved and legally unregulated. Despite these concerns, stem cell therapy is undeniably shaping a new direction for modern medicine one in which future treatment may not simply eliminate disease, but actively restore biological function and human vitality.

BHU's reputation tarnished

19 research papers returned in 4 years

Data manipulation and plagiarism exposed

Varanasi: Amidst efforts to maintain high level of research quality and academic integrity, serious irregularities were committed in the preparation of research papers in BHU. 19 research papers submitted to international journals by professors and researchers of various departments in the last four years have been returned. In the last five years, more than 75 research papers related to BHU professors have been out of international journals. The scholars who jointly conducted the research allege that many research papers were prepared with AI tools. The photographs taken with the microscope were manipulated. Research papers were published amidst irregularities like plagiarism (copy-paste), duplicate data, rights disputes. In the years 2022, 2023, 2024 and 2025, maximum number of 63 errors have been found in most of the research papers. The data for 2026 has not been released but it is being estimated that after the introduction of AI, many journals may face more problems in the scrutiny of research papers. All these research papers have been made public in many journals including Retraction Watch, Center of Biotechnology Information of National Library of Medicine. These research papers can also be seen on their website. These include research papers of BHU as well as those researches in which scientists or members of BHU have been included as researchers.

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"

FREE POLICY CONSULTATION

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

PUPILS TIMES
Core Committee
Anurag Shukla
Chief Editor
Shivprakash Pandey
Chief Publisher
Vikas Maurya
Co Publisher
Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS Printing Press,** UNIT NO.04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E) , MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**